>

Title: Alleged irregularities in the implementation of National Health Insurance Scheme in the country.

श्री नीरज शेखर (बलिया): सभापति जी, आज मैं अपने आपको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि साढ़े तीन साल लगातार प्रयास करने के बाद पहली बार ज़ीरो आवर में मेरा विषय उठा है। इसके लिए मैं अपने आपको बधाई देता हूँ।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार जो योजनाएँ बनाती है, बड़े धूमधाम से कहती है कि नरेगा लाए, यह लाए, वह लाए, उसका बड़ा प्रचार करती है कि पूरे देश में इनकी योजनाएँ बड़ी अच्छी चल रही हैं। 2007 में सरकार ने एक योजना शुरू की थी राष्ट्र स्वास्थ्य बीमा योजना। इसका बहुत प्रचार हुआ और लगातार इसका प्रचार भी हो रहा है, वित्त मंत्री जी कई बार इसके बारे में यहाँ बोल चुके हैं और समिति में भी यह बात आई है, लेकिन धरातल पर कहाँ तक यह योजना काम कर रही है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। आदरणीय नारायणसामी जी यहाँ बैठे हैं, वे हमारी बात को सरकार तक पहुँचाएँ। जो बलिया और गाज़ीपुर का जिला है, वहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। गाज़ीपुर जिले में करीब 23 लाख परिवारों का स्मार्ट कार्ड बनना था। उसमें से कुछ हज़ार लोगों का बना है। उसमें भी इतनी त्रुटियाँ हैं कि फोटो किसी की तो नाम किसी और का है। महिला पुरुष हो गया है और पुरुष महिला हो गए हैं। वह कार्ड बन ही नहीं रहा है। अगर केन्द्र सरकार यह कहती है कि राज्य सरकार को बनाने के लिए दे दिया गया है तो हर बात में यही होता है कि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार दोषी ठहराती है और राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार पूरा पैसा नहीं देती है। वहाँ जब योजना शुरू हुई तो गरीब आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि बीमा बहुत बड़ी चीज़ है। एक गरीब आदमी जब बीमार पड़ता है और उसको बीमारी में मदद मिल जाए तो उसको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। इलाहाबाद ज़िले में पिछले एक साल में केवल 80 हज़ार रुपये खर्च हुए। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि योजना कहाँ तक चली है। 22-23 लाख कार्ड बनने थे। उसमें से जो दो-तीन लाख कार्ड बने, वे अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं। कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए उसको तीन बार जाना पड़ता है। उसके लिए भी उसको पैसा देना है। हर बात में निराश होकर उसने कार्ड की आशा ही छोड़ दी है। ...(व्यवधान) वही मैं कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी योजना है और केन्द्र सरकार यह कह दे कि राज्य सरकार के ऊपर है, तो इससे बात नहीं बनेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर कुछ दबाव डाले कि वहाँ काम ठीक से किया जाए क्योंकि गरीबों के लिए योजना है। हर बार यह कह दें कि राज्य सरकार को करना है तो ठीक नहीं है। नरेगा का वही हाल है, बीमा योजना का वही हाल है, मिड डे मील का वही हाल है। अगर राज्य सरकार को आप कुछ नहीं कहेंगे तो यहाँ से पैसा मत भेजिए, उन पर कुछ दबाव डालिये जिससे वह बीमा योजना ठीक से चल सके।

सभापति महोदय : रोज़गार गारंटी कानून के बैनिफिशियरीज़ को भी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल करना है।

श्री नीरज शेखर : यह बीपीएल के लिए है।

सभापति महोदय : जो बीपीएल नहीं भी है और रोज़गार गारंटी कानून का बैनिफिशियरी है, उसको भी मिलने का कानून हो गया है।

श्री नीरज शेखर : उसको भी मिले, यही मैं आग्रह करता हूँ।

20.00 hrs.